



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 7 जून, 2006/17 ज्येष्ठ, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 जून, 2006

संख्या एच.एस.जी.-1(ए)3-6/2004.-हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (कर्मचारी अभिदायी भविष्य निधि) नियम, 2005 का प्रारूप, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 (2004 का 9) की धारा 61 के अधीन यथा अपेक्षित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 18 अक्टूबर, 2005 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 24 अक्टूबर, 2005 को प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेपों/सुझावों को आमन्त्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के दौरान कोई भी आक्षेप/सुझाव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 (2004 का 9) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (कर्मचारी अभिदायी भविष्य निधि) नियम, 2006 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों—

- (क) 'अधिनियम' से, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 (2004 का 9) अभिप्रेत है;
- (ख) 'प्राधिकरण' से, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी' से अधिनियम की धारा 11 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;
- (घ) 'उपलब्धियां' से, वेतन, छुट्टी संबलम या जीवन निर्वाह अनुदान, जैसा मूल अधिकारों में परिभाषित है, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हैं,—

- (i) महंगाई भत्ता, छुट्टी संबलम या जीवन निर्वाह अनुदान, यदि अनुज्ञेय हो;
- (ii) प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों को संदत्त की गई कोई मजदूरी, जो नियत मासिक वेतन द्वारा प्रतिदेय (रिन्म्यूरेटिड) न हो;
- (iii) विदेश सेवा की बाबत वेतन के रूप में प्राप्त किया गया कोई पारिश्रमिक;

(ङ) 'कुटुम्ब' से,—

- (i) पुरुष अभिदाता के मामले में, पत्नी, माता—पिता, संतान, अव्यस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्रों की विधवा और संतान तथा जहां अभिदाता के माता—पिता कोई जीवित न हों, पितामह—पितामही, अभिप्रेत है:

परन्तु यदि अभिदाता साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक् हो चुकी है या समुदाय, जिससे वह सम्बन्ध रखती है की रूढ़िजन्य विधि के अधीन उसकी भरण पोषण की हकदारी समाप्त हो चुकी है और वह परिमानतः आगे उन मामलों में जिनसे ये नियम सम्बन्धित हैं, अभिदाता के कुटुम्ब की सदस्य नहीं समझी जाएगी, जब तक कि अभिदाता तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित में यह सूचित नहीं कर देता है कि उसे इस रूप में ही बने रहने दिया जाए; और

- (ii) महिला अभिदाता के मामले में, पति, माता-पिता, संतान, अव्यस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और संतान तथा जहां अभिदाता के माता-पिता जीवित न हों, पितामह-पितामही अभिप्रेत हैं:

परन्तु यदि किसी महिला अभिदाता ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित में नोटिस द्वारा अपने पति को उसके कुटुंब से अपवर्जित करने की वांछा अभिव्यक्त की हो, तो पति तब से ही उन मामलों में जिनसे यह नियम सम्बन्ध रखते हैं अभिदाता के कुटुंब का सदस्य नहीं रहेगा, जब तक कि अभिदाता ऐसी सूचना को तत्पश्चात् लिखित में रद्द नहीं करती है।

**टिप्पण.**—‘संतान’ से धर्मज/अधर्मज संतान अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत दत्तक संतान, जहां दत्तक ग्रहण अभिदाता को शासित स्वीयविधि द्वारा मान्य है या प्रतिपाल्य, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8) के अधीन, प्राधिकरण के सेवक के साथ रहता हो और कुटुंब के सदस्य के रूप में माना जाता है और जिसे सेवक ने विशेष वसीयत द्वारा प्राकृतिक रूप में पैदा संतान के रूप में वही प्रस्थिति दी हो भी सम्मिलित है;

- (च) ‘सरकार’ से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (छ) ‘ब्याज’ से अभिदाता की भविष्य निधि पर संगणित जमा के अतिशेष पर प्रोद्भूत ब्याज अभिप्रेत है, जैसे कि ऐसे अतिशेष बचत बैंक खाता में जमा हों;
- (ज) ‘छुट्टी’ से अभिदाता को लागू मूल नियम या पुनरीक्षित छुट्टी नियम, 1972 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार की छुट्टी अभिप्रेत है;
- (झ) ‘भविष्य निधि’ से, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 31 के अधीन प्राधिकरण द्वारा स्थापित अभिदायी भविष्य निधि अभिप्रेत है;
- (ण) ‘सेवक’ से, निर्धारित कर्मचारी (वर्क चार्ज्ड) और दैनिक मजदूरी कर्मचारियों सहित प्रत्येक कर्मचारी अभिप्रेत है जिसने प्राधिकरण में एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण की है और ऐसा प्रत्येक सेवक भविष्य निधि में अभिदाय करने का पात्र होगा:

परन्तु कोई ऐसा सेवक जिससे अभिदाय करना अपेक्षित या अनुज्ञात हो या जो भविष्य निधि की किसी अन्य स्कीम का वास्तव में अभिदाता है, भविष्य निधि के अभिदाता के रूप में संयोजन करने या जारी रखने का पात्र नहीं होगा, जबकि उसे ऐसी भविष्य निधि को अभिदाय करने का अधिकार प्राप्त रहता है;

- (ट) ‘सेवा’ से, अभिदाता द्वारा प्राधिकरण की सेवा का कार्य ग्रहण करने की तारीख से की गई सेवा अभिप्रेत है;
- (ठ) ‘अभिदाता’ से, ऐसा सेवक अभिप्रेत है जिससे भविष्य निधि का अभिदाय करना अपेक्षित और अनुज्ञात हो; और
- (ड) ‘वर्ष’ से, वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

**3. भविष्य निधि की स्थापना.**—(1) प्राधिकरण एक भविष्य निधि स्थापित करेगा जिसमें प्रत्येक सेवक को एक वर्ष की सेवा के पश्चात् किसी राशि का, जो उसके उपलब्धियों के दस प्रतिशत से कम न हो, अभिदाय अपेक्षित हो:

परन्तु यदि अभिदाता ऐसी वांछा रखता हो तो वह भविष्य निधि में अधिक दर पर, जो उसके मूल वेतन से अधिक न हो अभिदाय कर सकेगा।

(2) नियत की गई ऐसे अभिदाय की रकम वर्ष के दौरान किसी समय एक बार कम की जा सकेगी और दो बार बढ़ाई जा सकेगी किन्तु घटाई गई ऐसी रकम इस नियम के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमा से कम नहीं होनी चाहिए।

4. पात्रता की शर्त.—ये नियम सिवाय उनको जो किसी अन्य भविष्य निधि नियमों के अधीन शासित हों या आते हों को छोड़कर प्राधिकरण के सभी सेवकों को लागू होंगे।

5. अभिदाय की वसूली.—(1) प्रत्येक सेवक जिसे ये नियम लागू होंगे, भविष्य निधि में अभिदाय करेगा। भविष्य निधि का अभिदाय प्रत्येक मास के वेतन बिल की रकम से कटौती के माध्यम से वसूल किया जाएगा और रकम पूर्ण रूप में होगी।

(2) नियम-3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अभिदाता, सिवाय उस अवधि के दौरान जब वह निलम्बनाधीन हो, भविष्य निधि में मासिक रूप से अभिदाय करेगा:

परन्तु अभिदाता उसके अपने विकल्प पर, छुट्टी के दौरान जिसमें उसे किसी छट्टी संबलम, के बराबर या आधे वेतन से अन्यून या आधा औसत वेतन मिलता हो, अभिदाय नहीं कर सकेगा:

परन्तु यह और कि अभिदाता को, निलम्बनाधीन अवधि के बीत जाने के पश्चात् यथापूर्वकरण पर, उसे एक मुश्त संदाय या किस्तों में किसी राशि जो उस अवधि के लिए संदेय अभिदाय के बकाया की अधिकतम रकम से अधिक न हो, के संदाय का विकल्प अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) यदि भविष्य निधि के लाभ में प्रविष्ट कोई सेवक, केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य अभिदायी या अनभिदायी भविष्य निधि में पहले से ही अभिदाता था तो यथास्थिति, उसके अभिदान की रकम और अन्य अभिदायी भविष्य निधि में सरकारी अंशदान या अनभिदायी निधि में उसके अभिदाय की रकम को उस पर ब्याज सहित उसके भविष्य निधि जमा खाते में अन्तरित किया जाएगा।

(4) यदि भविष्य निधि के लाभ में प्रविष्ट कोई सेवक, किसी अन्य सरकारी अभिदायी भविष्य निधि या अनभिदायी भविष्य निधि का पहले से ही अभिदाता था, तो, यथास्थिति, उसके अभिदान की रकम और अभिदायी भविष्य निधि में सरकारी अंशदान या अनभिदायी भविष्य निधि में उस पर ब्याज सहित उसके अभिदाय की रकम अन्य सरकार की सहमति के साथ उसकी भविष्य निधि के जमा में अन्तरित की जाएगी।

टिप्पण.—1 उप-नियम (3) और (4) के उपबन्ध, उस व्यक्ति को जो सेवा निवृत्त है और सेवा में व्यवधान के साथ या बिना, तत्पश्चात् पुनः नियोजित हुआ है अथवा उस व्यक्ति को जो पूर्व नियुक्ति संविदा पर कर रहा था, को लागू नहीं होंगे।

टिप्पण.—2 इस नियम के उपबन्ध, तथापि उन व्यक्तियों, जो बिना व्यवधान के चाहे अस्थायी या स्थायी रूप में नियुक्त किए गए हों, पदत्याग के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के अन्य सरकारी विभाग के अधीन या राज्य सरकार



के अधीन सेवा से त्याग-पत्र या छंटनी के पश्चात् इन नियमों का लागू रहन कर रहे हों, को लागू होंगे।

**टिप्पण.—3 उप-नियम (4) के उपबन्ध,** उन व्यक्तियों, जो सरकार के स्वामित्वाधीन या द्वारा नियंत्रित निगमित निकाय के या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वायत्त संस्था के अधीन सेवा से बिना किसी व्यवधान के अन्तरित हों, को भी यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

**6. विदेशी सेवा में स्थानान्तरण या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति.—**जब अभिदाता का विदेशी सेवा में स्थानान्तरण हुआ हो या उसको भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया हो, तो वह भविष्य निधि के नियमों के अधीन उसी रीति में रहेगा मानो कि उसका ऐसा स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति हुई ही न हो।

**7. नामांकन.—(1)** भविष्य निधि का सदस्य बनते समय अभिदाता, अपनी मृत्यु की दशा में एक या अधिक व्यक्तियों को उसकी भविष्य निधि में जमा रकम जो संदेय होने से पूर्व या संदेय हो किन्तु संदत्त न की गई हो को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करके, नामांकन कार्यालय के प्रधान के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेगा:

परन्तु यदि नामांकन करते समय अभिदाता का कुटुंब है, तो उसके कुटुंब के सदस्य के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि अभिदाता द्वारा किसी अन्य भविष्य निधि की बाबत किया गया नामांकन जिसमें वह इस भविष्य निधि का सदस्य बनने से पूर्व अभिदाय कर रहा था, यदि ऐसी अन्य निधि में उसके जमा की रकम को इस भविष्य निधि में उसके खाते में अन्तरित किया जाता है तो, इस नियम के अधीन तब तक सम्यक् रूप से दिया गया नामांकन समझा जाएगा जब तक कि वह इस नियम के अनुसार नामांकन नहीं करता।

(2) यदि अभिदाता उप-नियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है, तो वह नामांकन में प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय रकम या भाग को ऐसी रीति में विनिर्दिष्ट करेगा ताकि उसके भविष्य निधि खाते में जमा सारी रकम को किसी भी समय उनमें बांटा जा सके।

(3) प्रत्येक नामांकन इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप में किया जाएगा।

(4) अभिदाता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित में नोटिस भेजकर किसी भी समय नामांकन को रद्द कर सकेगा। अभिदाता, ऐसी सूचना के साथ या पृथकतः, इस नियम के उपबन्धों के अनुसार किया गया नया नामांकन भेज सकेगा।

(5) अभिदाता नामांकन में निम्नलिखित उपबन्ध कर सकेगा,—

(क) किसी विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिती के बारे में, अभिदाता से पूर्व उसकी मृत्यु होने की दशा में, उस नामनिर्देशिती को दिया गया अधिकार, नामांकन में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रदत्त हो जाएगा:

परन्तु यदि अभिदाता के कुटुम्ब में अन्य सदस्य हैं तो ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति ही वह अन्य सदस्य होंगे। जहां अभिदाता इस खण्ड के अधीन ऐसा अधिकार एक या अधिक व्यक्तियों को प्रदत्त करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को संदेय रकम या भाग को ऐसी रीति में विनिर्दिष्ट करेगा ताकि पूर्ण संदेय रकम नामनिर्देशितियों को बांटी जा सके; और

(ख) उसमें विनिर्दिष्ट आकस्मिकता के घटने के कारण नामांकन अविधिमान्य हो जायेगा।

परन्तु, नामांकन करते समय यदि अभिदाता के कुटुम्ब का केवल एक ही सदस्य है, तो वह नामांकन में यह उपबन्ध करेगा कि खण्ड (क) के अधीन अनुकल्पिक नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार, तत्पश्चात् उसके कुटुम्ब में अन्य सदस्य या सदस्यों के सम्मिलित होने की दशा में अविधिमान्य हो जाएगा।

(6) ऐसे नामनिर्देशिती जिसके बारे में उप-नियम (5) के खण्ड (क) के अधीन नामांकन में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है की मृत्यु होने पर या किसी घटना के घटने पर जिसके कारण उप-नियम (5) के खण्ड (ख) या उसके उपबन्धों के अनुसरण में नामांकन अविधिमान्य हो जाता है तो, अभिदाता तुरन्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, नामांकन को रद्द करने के लिए लिखित में नोटिस भेजेगा, साथ ही इस नियम के उपबन्धों के अनुसार नया नामांकन करेगा।

(7) अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और रद्दकरण हेतु दिया गया प्रत्येक नोटिस, इस सीमा जिस तक यह विधिमान्य है, उस तारीख जिसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसे प्राप्त करता है, से प्रभावी होगा।

8. अभिदाता के लेखे.—(1) प्रत्येक अभिदाता के नाम में एक खाता खोला जाएगा और अभिदाता को आबंटित भविष्य निधि खाता संख्या उसकी सेवा पुस्तिका में प्रविष्ट की जाएगी। अभिदाय की रकम, उस पर ब्याज, नियोजक का अंशदान तथा उस पर ब्याज, भविष्य निधि से अग्रिम और प्रत्याहरण, अभिदाता के लेखे में दर्शाया जाएगा।

(2) प्रत्येक अभिदाता को, वित्तीय वर्ष के बन्द होने पर प्रत्येक अभिदाता के लेखे में दिखाए गए अतिशेषों को दर्शाती विवरणी प्रत्येक वर्ष दी जाएगी।

9. प्राधिकरण द्वारा अंशदान.—प्राधिकरण, प्रत्येक मास के अन्त में प्रत्येक अभिदाता की भविष्य निधि खाते में, पूर्ण रूप में अभिव्यक्त उसकी उपलब्धियों के दस प्रतिशत के बराबर या जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, का अंशदान करेगा:

परन्तु ऐसी किसी अवधि की बाबत कोई भी अंशदान नहीं किया जाएगा जिसके लिए अभिदाता को नियमों के अधीन भविष्य निधि में अभिदाय न करने की अनुज्ञा दी जाती है या वह अभिदाय नहीं करता है।

10. ब्याज.—(1) प्राधिकरण, अभिदाता के जमा लेखे में ऐसी दर पर, जैसी सरकार समय-समय पर सामान्य भविष्य निधि के अभिदाय पर ब्याज के संदाय के लिए विहित करे, उसकी भविष्य निधि में जमा रकम पर ब्याज संदत्त करेगा।

(2) ब्याज, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को निम्नलिखित रीति में जमा किया जाएगा:-

- (i) चालू वर्ष के दौरान अग्रिम/निकाली गयी, यदि हो, की रकम से घटा कर पूर्वगामी वर्ष के 31 मार्च तक अभिदाता के जमा की रकम पर;
- (ii) चालू वर्ष में निकाली गई राशियों पर, चालू वर्ष के प्रथम अप्रैल से निकालने के मास के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिवस तक ब्याज;
- (iii) पूर्वगामी वर्ष के 31 मार्च के पश्चात् अभिदाता के लेख में जमा की गई सभी राशियों पर, जमा की तारीख से चालू वर्ष के 31 मार्च तक ब्याज;
- (iv) ब्याज की कुल रकम को रुपए के निकटतम पूर्णांकित किया जाएगा (पचास पैसे को अगले उच्च रुपए के रूप में गिना जाना);

परन्तु जब अभिदाता के खाते में जमा रकम संदेय हो जाती है तो इस नियम के अधीन उसके ऊपर ब्याज, यथास्थिति, केवल चालू वर्ष के प्रारम्भ की अवधि की बाबत या जमा किए जाने की तारीख से जिसको अभिदाता के खाते में जमा रकम संदेय हो जाती है, जमा किया जाएगा।

(3) नियम 21 के अधीन संदत्त की जाने वाली किसी रकम के अतिरिक्त उस पर ब्याज, उस पर पूर्ववर्ती मास के अन्त तक जिसमें संदाय किया गया है या छह मास के पश्चात् जिस मास में ऐसी रकम संदेय होती है इन अवधियों में जो भी कम हो, व्यक्ति जिसे ऐसी रकम संदत्त की जानी है, को संदेय होगी:

परन्तु जहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उस व्यक्ति या उसके अभिकर्ता को वह तारीख सूचित कर दी है जिस पर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगद में संदाय करने को तैयार है, या उस व्यक्ति को संदाय चैक में डाक द्वारा भेज दिया हो तो ब्याज, यथास्थिति, ऐसी सूचित तारीख के पूर्ववर्ती मास के अन्त या चैक को डाक द्वारा भेजने की तारीख से संदेय होगा।

11. भविष्य निधि से अग्रिम.—(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, किसी अभिदाता को, अग्रिम का संदाय, जो छह मास के वेतन से अनधिक या अभिदाता की भविष्य निधि के खाते में ब्याज सहित अभिदाय की रकम के जमा का आधा, जो भी कम हो, निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए मंजूर कर सकेगा:-

- (क) जहां आवश्यक हो, अभिदाता और उसके कुटुंब के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप में निर्भर किसी व्यक्ति के यात्रा भत्ते सहित बीमारी, परिशोध या निःशक्तता के सम्बन्ध में व्यय संदत्त करने;
- (ख) जहां आवश्यक हो, अभिदाता और उसके कुटुंब के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप में निर्भर किसी व्यक्ति के यात्रा भत्ते सहित, उच्च शिक्षा के व्यय की निम्नलिखित मामलों में पूर्ति करना, अर्थात:-

- (i) उच्च विद्यालय स्तर से आगे भारत के बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए; और
- (ii) उच्च विद्यालय स्तर से आगे भारत में किसी चिकित्सा, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी अथवा विशेषज्ञादि पाठ्यक्रम हेतु; किन्तु वह पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम के लिए न हो;

- (ग) अभिदाता की हैसियत अनुसार उपयुक्त मापमान पर आबद्धकर व्ययों का संदाय करने हेतु जिसे रुढ़िजन्य प्रथा द्वारा अभिदाता को सगाई या विवाहों, अत्येष्टियों अथवा अन्य संस्कारों के सम्बन्ध में उपगत करना होता है;
- (घ) अभिदाता, उसके कुटुंब के किसी सदस्य या किसी व्यक्ति जो वास्तविक रूप में उस पर निर्भर हो द्वारा या के विरुद्ध संस्थित की गई विधिक कार्यवाहियों के खर्च को पूरा करने के लिए किसी अन्य सरकारी स्रोत से उसी प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय किसी अग्रिम के अतिरिक्त इस मामले में अग्रिम को उपलब्ध किए जाने हेतु;
- (ङ) जहां अभिदाता को उसके द्वारा किसी अभिकथित शासकीय अवचार की बाबत जांच में स्वयं की प्रतिरक्षा के लिए विधिक व्यवसायी को नियुक्त करना पड़ता है, के लिए रक्षा खर्च की पूर्ति करने हेतु;
- (च) उपभोक्ता ड्यूरेवल वस्तुएं जैसे कि टेलीवीजन, वीडियो/वीडियो, धुलाई मशीन, कुकिंग रेंज, गीजर और कम्प्यूटर खरीदने हेतु।

(2) प्राधिकरण, विशेष परिस्थितियों में, किसी अभिदाता को, किसी अग्रिम के संदाय को मंजूर कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि सम्बद्ध अभिदाता को उप-नियम (1) में वर्णित उन कारणों से भिन्न के लिए अग्रिम की अपेक्षा है।

(3) किसी अभिदाता को विशेष कारणों को अभिलिखित करने के सिवाय, या जब तक पूर्व अग्रिम की अन्तिम किस्त का प्रतिसंदाय नहीं करता, उप-नियम (1) में अधिकथित सीमा से अधिक अग्रिम प्रदान नहीं किया जाएगा:

परन्तु अग्रिम किसी भी दशा में अभिदाता की भविष्य निधि में कुल जमा अभिदाय की रकम और उस पर ब्याज से अधिक नहीं होगा।

(4) किसी पूर्व अग्रिम की अन्तिम किस्त का प्रतिसंदाय पूरा होने से पहले जब उप-नियम (3) के अधीन अग्रिम मंजूर किया गया हो तो, वसूल न किए गए किसी पूर्व अग्रिम का अतिशेष, ऐसे मंजूर अग्रिम के साथ जोड़ा जाएगा और वसूली के लिए किस्तों समेकित रकम के सन्दर्भ में नियत की जाएंगी।

12. अग्रिमों की वसूली.— (1) अभिदाता से अग्रिम ऐसी मासिक बराबर किस्तों में वसूल किया जाएगा जैसा मुख्य कार्यकारी अधिकारी निदेश दें, किन्तु ऐसी संख्या बारह से कम और बीस से अधिक नहीं होगी, जब तक कि अभिदाता बारह से कम किस्तों में संदाय करने का निर्णय न ले। विशेष मामलों में, जहां अग्रिम की रकम, नियम 11 के उप-नियम (3) के अधीन अभिदाता के छह मास के वेतन से अधिक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसी किस्तों की संख्या चौबीस से अधिक किन्तु किसी भी दशा में छत्तीस से अनधिक नियत कर सकेगा। अभिदाता, अपने विकल्प पर, विहित की गई किस्तों की संख्या से कम में प्रतिसंदाय कर सकेगा।

(2) वसूली जिसमें अग्रिम लिया गया था आगामी मास, के लिए वेतन जारी होने के साथ प्रारम्भ होगी। अभिदाता की सहमति के सिवाय तब वसूली नहीं की जाएगी जब वह, यथास्थिति, जीवन निर्वाह अनुदान प्राप्त कर

रहा हो या कलैन्डर मास में दस दिन या अधिक की छुट्टी पर हो जिसमें या तो कोई छुट्टी संबलन नहीं है या छुट्टी संबलन के समान या आधे वेतन या आधे वेतन से अन्यून है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा, अभिदाता के लिखित अनुरोध पर, अग्रिम की वसूली के दौरान या अभिदाता को वेतन प्रदान करते हुए, वसूली स्थगित की जा सकेगी।

13. अग्रिम का सदोश उपयोग.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास संदेह का कारण है कि नियम 11 के अधीन भविष्य निधि से निकाला गया अग्रिम, उस प्रयोजन जिसके लिए धन निकालने की मंजूरी दी गई थी, से भिन्न के लिए, उपयोग किया जा चुका है, तो वह अभिदाता को अपने संदेह के कारणों को संसूचित करेगा और उससे ऐसी संसूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में स्पष्ट करने की अपेक्षा करेगा कि क्या अग्रिम उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए धन निकालने की मंजूरी दी गई थी। यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अभिदाता द्वारा पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर दिए गए स्पष्टीकरण से समाधान नहीं होता तो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिदाता को प्रश्नगत रकम को तुरन्त भविष्य निधि में प्रतिसंदत्त करने का निदेश देगा या, व्यतिक्रम होने में, अभिदाता के छुट्टी पर होने पर भी उसके परिवेत्तन से एक मुश्त राशि में रकम की कटौती द्वारा, वसूल किए जाने के आदेश करेगा। यदि फिर भी, प्रतिसंदत्त किए जाने वाली कुल रकम, अभिदाय किए जाने वाले परिवेत्तन के आधे से अधिक हो, तो वसूलियां उसके परिवेत्तन के अर्धांश की मासिक किस्तों में उसके द्वारा संपूर्ण रकम के प्रतिसंदत्त होने तक की जाएगी।

टिप्पण-1 इस नियम में 'उपलब्धियां पद' में जीवन निर्वाह अनुदान सम्मिलित नहीं है।

14. भविष्य निधि से प्रत्याहरण.—(1) उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्वधीन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किसी भी समय नियम 11 के उप-नियम (3) के अधीन विशेष कारणों के लिए प्रत्याहरण मंजूर किया जा सकेगा,—

(I) अभिदाता की पन्द्रह वर्ष (खण्डित सेवा काल सहित, यदि कोई हो) की सेवा पूर्ण होने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर, उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, भविष्य निधि में अभिदाता के नाम में जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम से, निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:—

(क) जहां आवश्यक हो अभिदाता या अभिदाता की संतान के यात्रा व्ययों सहित, उच्च शिक्षा के व्यय की निम्नलिखित मामलों में पूर्ति करने, अर्थात्:—

- (i) उच्च पाठशाला स्तर से ऊपर के शैक्षणिक, तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु, भारत से बाहर शिक्षा के लिए; और
- (ii) उच्च पाठशाला स्तर से ऊपर भारत में किसी चिकित्सीय, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञीय पाठ्यक्रम के लिए; और

(ख) अभिदाता या उसके पुत्रों अथवा पुत्रियों और उस पर वास्तविक रूप में आश्रित किसी अन्य महिला सम्बन्धी की सगाई/विवाह के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति करने;

(ग) अभिदाता और उसके कुटुंब के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप में आश्रित किसी व्यक्ति के यात्रा व्यय, जहां आवश्यक हो, के सहित बीमारी के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति करने;

(घ) उपभोक्ता डयुरेबलज जैसे टेलीवीजन, वीडियोआर0/वीडियोपी0, कपडे धोने की मशीन, रसोई का सामान, गीजर और कम्प्यूटर के लागत की पूर्ति करने।

(II) अभिदाता की सेवा के दौरान, भविष्य निधि में उसके नाम में जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए अर्थात्:-

(क) स्थल की कीमत सहित या प्लाट के आबंटन हेतु या प्राधिकरण द्वारा फ्लैट या सहकारी सोसाइटी के भवन सहित, उसके निवास के लिए उपयुक्त गृह का विनिर्माण या अर्जन करने या बना बनाया फ्लैट लेने;

(ख) उसके निवास के लिए उपयुक्त गृह के विनिर्माण या अर्जन करने या बने बनाए फ्लैट के लिए अभिव्यक्त रूप में लिए गए ऋण की परादेय रकम का प्रतिसंदाय करने;

(ग) अभिदाता द्वारा पहले से स्वामित्व में या अर्जित गृह या फ्लैट के पुनः विनिर्माण या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने;

(घ) कार्य के स्थान से भिन्न स्थान पर पैतृक गृह या कार्य के स्थान से भिन्न स्थान पर प्राधिकरण से ऋण की सहायता से बनाए गए गृह के नवीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन अथवा अनुरक्षण करने;

(ङ) उसके निवास के लिए गृह स्थल खरीदने और उस पर गृह विनिर्माण करने; और

(च) खण्ड (ङ) के अधीन खरीदे गए स्थल पर गृह का विनिर्माण करने।

टिप्पण.-1 खण्ड (II) के उप-खण्ड (ख) के अधीन मंजूर किए गए प्रत्याहरण की रकम, आवेदन की तारीख को खण्ड (II) के उप-खण्ड (क) के अधीन पूर्व प्रत्याहरण की रकम के साथ, पूर्व प्रत्याहरण की रकम घटाकर अतिशेष से 3/4 से अनधिक होगी।

टिप्पण.-2 इस नियम के अधीन एक प्रयोजन के लिए केवल एक प्रत्याहरण ही अनुज्ञात किया जाएगा। किन्तु विभिन्न संतानों का विवाह या शिक्षा अथवा विभिन्न अवसरों पर बीमारी या गृह या फ्लैट के और परिवर्धन तथा परिवर्तन को एक प्रयोजन नहीं माना जाएगा। खण्ड (II) के उप-खण्ड (क) या (च) के अधीन उसी गृह के पूर्ण करने के लिए द्वितीय या पश्चात्पूर्वी प्रत्याहरण को, टिप्पण-1 के अधीन अधिकथित परिसीमा तक अनुज्ञात किया जाएगा।

टिप्पण.-3 इस नियम के अधीन प्रत्याहरण को मंजूर नहीं किया जाएगा यदि नियम-11 के अधीन अग्रिम उसी प्रयोजन के लिए और उसी समय मंजूर किया जा रहा है।

15. प्रत्याहरण के लिए शर्तें.- (1) अभिदाता द्वारा उसकी भविष्य निधि में उसके जमा की रकम से नियम 14 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई राशि आमतौर से भविष्य

निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की रकम के आधे या छः मास का वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। फिर भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नियम 14 के उप-नियम (1) के खण्ड (I) के अधीन प्रत्याहरणों की दशा में प्रत्याहरण की रकम की सीमा तीन चौथाई से अधिक और खण्ड (II) के अधीन प्रत्याहरणों की दशा में भविष्य निधि में अभिदाता के नाम पर जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम से 90 प्रतिशत तक की मंजूरी निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए दे सकेगा,—

- (i) उद्देश्य जिसके लिए प्रत्याहरण किया जा रहा है;
- (ii) अभिदाता की प्रास्थिति ; और
- (iii) अभिदाता के नाम जमा अभिदाय और उस पर ब्याज सहित रकम।

16. अग्रिम का प्रत्याहरण में संपरिवर्तन.—अभिदाता जिसने, नियम 14 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए नियम 11 के अधीन पहले ही अग्रिम प्रत्याहृत किया है या भविष्य में निकालना है, स्वविवेकानुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्बोधित लिखित अनुरोध द्वारा इसके विरुद्ध परादेय अतिशेष को नियम 14 और 15 में अधिकथित शर्तों हेतु उसका समाधान होने पर अन्तिम प्रत्याहरण में संपरिवर्तित करवा सकेगा।

टिप्पण.—नियम 15 के उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए, संपरिवर्तन और अग्रिम की परादेय रकम के समय पर अभिदाता के लेखे में उसके नाम जमा उस पर ब्याज सहित अभिदाय की रकम को अतिशेष के रूप में लिया जाएगा। प्रत्येक प्रत्याहरण को एक पृथक प्रत्याहरण के रूप में माना जाएगा और एक से अधिक संपरिवर्तन की दशा में वही नियम लागू होगा।

17. भविष्य निधि में अन्तिम प्रत्याहरण का संचयन.—जब अभिदाता सेवा छोड़ देता है, तो भविष्य निधि में उसके नाम जमा रकम, नियम 20 के अधीन किसी कटौती के अध्वधीन, उसे संदेय होगी:

परन्तु अभिदाता, जिसको सेवा से पदच्युत किया गया हो और तत्पश्चात् सेवा में यथा—पूर्वकरण किया जाता है, यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित है, इस नियम के अनुसरण में, भविष्य निधि से उसे संदत्त किसी रकम का नियम 10 में उपबंधित दर से और नियम 18 के परंतुक में उपबंधित रीति में उस पर ब्याज के साथ प्रति संदाय करेगा। इस प्रकार प्रतिसंदत्त रकम भविष्य निधि में उसके नाम जमा की जाएगी, उस पर ब्याज सहित भाग, जो उसके अभिदाय को व्यपदिष्ट करता है, और भाग जो प्राधिकरण के अंशदान को उस पर ब्याज के साथ व्यपदिष्ट करता है, नियम 8 में उपबंधित रीति में लेखे में लिया जाएगा।

18. अपवाद.—अभिदाता, जिसे संविदा पर नियुक्त किया गया है या जो सेवा से निवृत्त हुआ है और उसके पश्चात् सेवा में व्यवधान या बिना व्यवधान के पुनः नियोजित किया गया है, जब सेवा में बिना व्यवधान के राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग में नए पद पर अन्तरित किया जाता है (जिसमें उसे भविष्य निधि नियमों के अन्य संवर्ग द्वारा शासित किया जाता है) और उसके पूर्व पद के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, का सेवा को छोड़ना नहीं माना जाएगा। ऐसी दशा में उसका अभिदाय और प्राधिकरण का अंशदान, उस पर ब्याज के साथ निम्नलिखित को अन्तरित किया जाएगा,—

- (क) यदि नया पद सरकार के अन्य विभाग में है तो भविष्य निधि के नियमों के अनुसार उसकी अन्य भविष्य निधि के खाते में, या

- (ख) यदि नया पद राज्य सरकार के अधीन है और राज्य सरकार उसके अभिदायों, प्राधिकरण के अंशदान और ब्याज के ऐसे अन्तरण को साधारण या विशेष आदेश द्वारा सहमति दे, संबद्ध राज्य सरकार के अधीन नए लेखे में अन्तर्लिखित किया जाएगा।

19. अभिदाता की सेवा निवृत्ति.—जब अभिदाता,—

- (क) सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला जाता है, या
- (ख) जब छुट्टी पर है, या सेवा निवृत्त होना अनुज्ञात किया गया है या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, तो भविष्य निधि में उसके नाम पर जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम, उसके द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस निमित्त किए गए आवेदन पर, अभिदाता को संदेय हो जाएगी:

परन्तु अभिदाता, यदि कार्य पर वापिस आता है, तो सिवाय जहां प्राधिकरण अन्यथा विनिश्चय करे, भविष्य निधि से उसे संदत्त की गई रकम को, जैसा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, इस नियम के अनुसरण में नियम 10 में उपबंधित दर से उस पर ब्याज सहित, नकद या प्रतिभूतियों में, किस्तों द्वारा या अन्यथा उसके परिवेत्तन से वसूली द्वारा या अन्यथा, नियम 11 के उप-नियम (3) के अधीन अग्रिम, जिसे प्रदान किए जाने के लिए विशेष कारण अपेक्षित है, अपने नाम पर भविष्य निधि के खाते में प्रतिसंदत्त करेगा।

20. अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया.—नियम 20 के अधीन किसी कटौती के अध्यक्षीन, उसके नाम पर जमा रकम के संदेय होने से पूर्व, या जहां रकम संदेय हो चुकी हो, और संदाय किए जाने से पूर्व अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर ;

(i) जब अभिदाता कुटुंब छोड़ जाता है,—

- (क) यदि नियम 7 के उपबन्धों के अनुसार अभिदाता द्वारा उसके कुटुंब के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में है, तो भविष्य निधि में उसके नाम पर जमा रकम या उसका भाग जिससे नाम निर्देशन सम्बन्धित है, उसके नामनिर्देशित या नामनिर्देशितियों को नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में संदेय होगी;

- (ख) यदि अभिदाता के कुटुंब के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में कोई ऐसा नामनिर्देशन नहीं है या यदि ऐसा नामनिर्देशन भविष्य निधि में उसके नाम पर जमा रकम के केवल कुछ भाग से सम्बन्धित है तो, यथास्थिति, सारी रकम या उसका भाग जो नाम निर्देशन से सम्बन्धित नहीं है उसके कुटुंब के सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में किसी नामनिर्देशन में किसी बात से तात्पर्यित नहीं है, उसके कुटुंब के सदस्यों में बराबर हिस्सों में संदेय होगी:



परन्तु यदि निम्नलिखित (1), (2), (3) और (4) मदों में विनिर्दिष्ट से भिन्न कुटुंब का कोई और सदस्य हो, तो निम्नलिखित को कोई हिस्सा संदेय नहीं होगा:-

- (1) पुत्र, जो व्यस्कता प्राप्त कर चुके हों;
- (2) मृतक पुत्र के पुत्र, जो व्यस्कता प्राप्त कर चुके हों ;
- (3) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों;
- (4) मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियां, जिनके पति जीवित हों:

परन्तु यह भी कि मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चा या बच्चे आपस में केवल उस हिस्से के बराबर भाग प्राप्त करेंगे जो अभिदाता का उत्तरजीवी होने पर उस पुत्र ने प्राप्त किया होता और प्रथम परन्तुक की मद (1) के उपबन्धों से छूट प्राप्त की होती।

- (ii) जब अभिदाता का कोई कुटुंब न हो, और यदि नियम 7 के उपबन्धों के अनुसार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में रहता है; तो भविष्य निधि में उसके नाम पर जमा रकम या उसका भाग जिससे नामनिर्देशन सम्बन्धित है, नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नामनिर्देशिनी या नाम-निर्देशितियों में संदेय होगा।

**21. कटौती.**—इस शर्त के अधीन कि जब तक भविष्य निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम को भविष्य निधि से संदत्त नहीं कर दिया जाता तब तक कोई भी ऐसी कटौती नहीं की जाएगी जो नियम 9 और 10 के अधीन प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी अंशदान से, उस पर ब्याज सहित की रकम से अधिक जमा को कम कर देती है,—

- (I) सरकार उसमें से कटौती और प्राधिकरण को संदाय निदेशित कर सकेगी,—

- (i) यदि अभिदाता को अवचार, दिवालियापन या अदक्षता के कारण सेवा से पदच्युत किया हो तो ऐसे अंशदान और ब्याज के रूप में समस्त रकमें:

परन्तु जहां सरकार का समाधान हो जाता है कि इस प्रकार की कटौती से अभिदाता के लिए असाधारण कठिनाई होगी, तो यह आदेश द्वारा, ऐसी कटौती और रकम जो ऐसे अंशदान और ब्याज के दो तिहाई रकम से अनधिक हो, जो अभिदाता को संदेय होता, यदि वह चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुआ होता, से छूट दे सकेगी:

परन्तु यह और कि यदि कोई ऐसा पदच्युत करने का आदेश, तत्पश्चात् रद्द हो जाता है, तो इस प्रकार की गई कटौती की रकम, उसके सेवा में पुनः स्थापन पर, भविष्य निधि में उसके नाम पर प्रतिस्थापित की जाएगी।

- (ii) ऐसे अंशदान और ब्याज के रूप में समस्त रकमें, यदि अभिदाता ऐसी सेवा की हैसियत के प्रारम्भ होने के पांच वर्ष के भीतर सेवा से त्याग पत्र देता है अथवा मृत्यु, सेवा निवृत्ति या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उसे आगे सेवा करने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने या पद समाप्त होने या स्थापन की कटौती के कारण से अन्यथा, प्राधिकरण का कर्मचारी नहीं रहता।

- (II) सरकार, प्राधिकरण के प्रति अभिदाता द्वारा उपगत दायित्वाधीन देय किसी रकम से प्राधिकरण को संदत्त और उससे कटौती करने के निदेश दे सकेगी।

टिप्पण.—1 इस नियम के खण्ड (1) उप-खण्ड (ii) के प्रयोजन के लिए,—

- (क) पांच वर्ष की अवधि की गणना, प्राधिकरण के अधीन अभिदाता से लगातार सेवा के प्रारम्भ से की जाएगी;
- (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन निगमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वायत्त संस्था में अन्य विभाग में नियुक्ति के कारण बिना किसी व्यवधान के और प्राधिकरण की उचित अनुज्ञा के साथ, सेवा से दिए गए त्याग-पत्र को प्राधिकरण की सेवा से त्याग-पत्र नहीं समझा जाएगा।

टिप्पण.—2 इस नियम के अधीन, उसमें निर्दिष्ट रकमों के बारे में उस अग्रिम को मंजूर करने, जिसे प्रदान करने के लिए नियम 11 के उप-नियम (3) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित है, सरकार की शक्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा निष्पादित की जा सकेंगी।

22. भविष्य निधि में रकम के संदाय की रीति.—(1) जब अभिदाता के नाम पर भविष्य निधि में जमा रकम या नियम 20 के अधीन कटौती के पश्चात् उसमें अतिशेष संदेय हो जाता है, तो मुख्य लेखा अधिकारी का समाधान होने के पश्चात् यह कर्तव्य होगा कि जब इस नियम के अधीन किसी ऐसी कटौती को निदेशित न किया गया हो, तो इस निमित्त लिखित आवेदन प्राप्त होने पर संदाय करते हुए कोई कटौती न की जाए।

(2) अभिदाता को भविष्य निधि से रकम के प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रत्येक अभिदाता को आवश्यक प्ररूप भेजेगा। अभिदाता, मुख्य लेखा अधिकारी के माध्यम से, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुरन्त अभिदाता को अन्तिम संदाय मंजूर करेगा।

23. उन विषयों जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, को अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 का लागू होना.—नियमों के अधीन शासित प्राधिकरण के कर्मचारियों को उन विषयों के बारे में जो विनिर्दिष्टता उपबन्धित नहीं हैं और जो इन नियमों के अधीन बनाए गए उपबन्धों के साथ असंगत नहीं हैं, समय-समय पर यथा संशोधित अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के उपबन्ध लागू होंगे।

24. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अभिदायी भविष्य निधि नियम, 1982 को एतद्वारा निरसित किया जाता है:

परन्तु ऐसे निरसित किए गए नियमों के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची

[नियम 7(3) देखें]

लेखा संख्या—

मैं—एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति(यों), जो हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (कर्मचारी अभिदायी भविष्य निधि) नियम, 2006 के नियम 2 में यथापरिभाषित, मेरे कुटुंब का सदस्य/गैर-सदस्य है, को भविष्य निधि में मेरे नाम जमा उस रकम को, जो संदेय हो चुकी है या संदेय होने वाली है पर संदत्त नहीं की गई है, जैसा नीचे उपदर्शित है, से पूर्व मेरी मृत्यु होने की दशा में, उसे प्राप्त करने के लिए नाम-निर्दिष्ट करता हूँ।

| नाम<br>निर्देशिती(यों) के<br>नाम और पूरा<br>पता | अभिदाता के<br>साथ सम्बन्ध | नाम<br>निर्देशिती(यों)<br>की आयु | प्रत्येक नाम—<br>निर्देशिती को<br>संदेय हिस्सा | आकस्मिकताएं<br>जिनके घटने<br>पर नाम—<br>निर्देशन<br>अविधिमान्य<br>होगा | व्यक्ति(यों),<br>का नाम, पता<br>और सम्बन्ध,<br>यदि कोई हो,<br>जिसको<br>अभिदाता की<br>मृत्यु से पूर्व की<br>दशा में<br>उसका/उसकी<br>नाम-निर्देशिती<br>का अधिकार<br>हस्तान्तरित<br>होता है | यदि नाम<br>निर्देशिती<br>कुटुंब का<br>सदस्य<br>नहीं है,<br>जैसा<br>नियम 2 में<br>उपबन्धित<br>है, कारण<br>उपदर्शित<br>करें |
|---|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| 1   | 2                         | 3                                | 4  | 5  | 6  | 7   |

आज तारीख—200 , के दिन पर ।

अभिदाता के हस्ताक्षर

नाम बड़े अक्षरों में—

पदनाम—

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

नाम और पता

1

2.

(प्ररूप की पृष्ठ पीठ)

कार्यालय प्रधान/वेतन और लेखा कार्यालय द्वारा प्रयोग के लिए स्थान \_\_\_\_\_

श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_

द्वारा नाम निर्देशन \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

नाम निर्देशन की प्राप्ति की तारीख \_\_\_\_\_

कार्यालय प्रधान/वेतन और लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

अभिदाता के लिए अनुदेश—

(क) आपका नाम लिखा जाएगा।

(ख) निधि का नाम उपयुक्त रूप में भरा जाए।

(ग) 'कुटुंब' शब्द की परिभाषा, जैसी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (कर्मचारी अभिदायी भविष्य निधि) नियम, 2005 में दी गई है, को नीचे दोहराया गया है।

'कुटुंब' से,—

(i) पुरुष अभिदाता के मामले में, पत्नी या पत्नियां, माता-पिता, संतान, अव्यस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और संतान तथा जहां अभिदाता के माता-पिता जीवित न हों, पितामह-पितामही:

परन्तु यदि अभिदाता साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप में पृथक हो चुकी है या समुदाय जिससे वह सम्बन्ध रखती है, की रूढ़िजन्य विधि के अधीन उसकी भरण-पोषण की हकदारी समाप्त हो चुकी है, और वह आगे उन मामलों में जिनसे ये नियम सम्बन्धित हैं, अभिदाता के कुटुंब की सदस्य नहीं समझी जाएगी जब तक कि अभिदाता सत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित में यह सूचित नहीं कर देता है कि उसे इस रूप में ही बने रहने दिया जाए; और

(ii) महिला अभिदाता के मामले में पति, माता-पिता, संतान, अव्यस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और संतान तथा जहां अभिदाता के माता-पिता जीवित न हों, पितामह-पितामही:

परन्तु यदि किसी महिला अभिदाता ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित में सूचना द्वारा अपने पति को उसके कुटुंब से अपवर्जित करने की वांछा अभिव्यक्त की हो, तो पति तब से ही उन मामलों में जिनसे ये नियम सम्बन्ध रखते हैं, अभिदाता के कुटुंब का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि अभिदाता, ऐसी सूचना को तत्पश्चात् लिखित में रद्द नहीं करती है।

**टिप्पण.—**‘संतान’ से धर्मज/अधर्मज संतान अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत, दत्तक संतान, जहां दत्तक—ग्रहण, अभिदाता को शासित स्वीय विधि द्वारा मान्य हो या प्रतिपाल्य जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8) के अधीन, प्राधिकरण के सेवक के साथ रहता हो और कुटुंब के सदस्य के रूप में माना जाता है और जिसे सेवक ने विशेष वसीयत द्वारा प्राकृतिक रूप में पैदा सन्तान के रूप में, वही प्रास्थिति दी हो, भी सम्मिलित है।

- (घ) स्तंभ 4 यदि केवल एक व्यक्ति को नाम—निर्देशित किया है तो नाम—निर्देशिनी के सामने ‘पूर्ण रूप में’ शब्द लिखे जाने चाहिए। यदि एक से अधिक व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए हैं, तो भविष्य निधि की सम्पूर्ण रकम से प्रत्येक नाम—निर्देशिनी को संदेय अंश विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
- (ङ) स्तंभ 5 में नाम निर्देशिनी(यों) की मृत्यु आकस्मिता के रूप में वर्णित नहीं की जानी चाहिए।
- (च) स्तंभ 6 में अपना नाम वर्णित न करें।
- (छ) आपके हस्ताक्षर होने के पश्चात्, किसी नाम का अन्तःस्थापन रोकने के लिए अन्तिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर टेढ़ी रेखा खींचें।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
सचिव।

*[Authoritative English text of this Department Notification No. HSG-1A(3)-6/2004, dated 01.06.2006 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]*

## HOUSING DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 1st June, 2006*

**No. HSG-1A(3)-6/2004.**—Whereas the draft of the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (Employees Contributory Provident Fund) Rules, 2006 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) dated 24<sup>th</sup> Oct., 2005 *vide* this Department notification of even number dated 18<sup>th</sup> Oct., 2005 for inviting the objections and suggestions from the general public as required under section 61 of the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004 (Act No. 9 of 2004) within a period of 30 days from the date of publication.

And whereas, no objection/suggestion has been received during the stipulated period by the State Government.

Now, therefore, in exercise of powers conferred under section 61 of the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004 (Act No. 9 of 2004), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the purposes of the aforesaid Act, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (Employees Contributory Provident Fund) Rules, 2006.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Definitions.*— In these rules unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004 (Act No. 9 of 2004);
- (b) “Authority” means Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority;
- (c) “Chief Executive Officer” means the Chief Executive Officer of the Authority appointed under section 11 of the Act ;
- (d) “Emoluments” means pay, leave salary or subsistence grant as defined in the Fundamental Rules and includes,—
  - (i) dearness allowance, leave salary or subsistence grant, if admissible;
  - (ii) any wages paid by the Authority to the employees not remunerated by fixed monthly pay; and
  - (iii) any remuneration of the nature of pay received in respect of foreign service;
- (e) “family” means—
  - (i) in the case of a male subscriber, the wife, parents, children, minor brothers, un-married sisters, deceased sons widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grand parent :

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community, to which she belongs to be entitled to maintenance and she shall be henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber’s family in matters to which these rules relates unless the subscriber subsequently intimates, in writing to the Chief Executive Officer that she shall continue to be so regarded; and

- (ii) in the case of female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased sons widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grand parent:

Provided that if a female subscriber by notice in writing to the Chief Executive Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no

longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

**NOTE.**—"child" means legitimate/illegitimate child and includes adopted child, where adoption is recognized by personal law governing the subscriber, or a ward under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), who lives with the servant of the Authority and is treated as a member of the family and to whom the servant has, through a special will, given the same status as that of a natural born child.

- (f) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;
- (g) "interest" means interest accrued on the balance at credit of a subscriber to the Provident Fund calculated as if such balance were deposit in the saving bank account;
- (h) "leave" means any kind of leave recognized by the fundamental Rules or Revised Leave Rules, 1972 applicable to the subscriber;
- (i) "Provident Fund" means the Contributory Provident Fund established by the Authority under section 31 of the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004;
- (j) "servant" means every employee including work charged and daily waged employees who has completed one year's continuous service in the Authority and every such servant shall be eligible to subscribe to the Provident Fund:

Provided that no such servant who is required or permitted to contribute or who is actually contributor to any other scheme of Provident Fund shall not be eligible to join or continue as a subscriber to the provident Fund, while he retains the right to subscribe to such a provident Fund;

- (k) "service" means service of the subscriber from the date of his joining the service of the Authority;
- (l) "subscriber" means a servant who is required or permitted to subscribe to the Provident Fund; and
- (m) "year" means the financial year.

**3. Establishment of Provident Fund.**—(1) The Authority shall establish a Provident Fund to which every servant shall be required to subscribe after one year of service, any sum not less than ten percent of his emolument :

Provided that a subscriber if he so desires may contribute to the provident Fund at a higher rate not exceeding his basic pay.

(2) The amount of subscription so fixed may be reduced once at any time and enhanced twice during the course of the year but amount so reduced should not be less than limit specified in sub-rule (1) of this rule.

4. *Condition of eligibility.*—These rules shall apply to all servants of the Authority except those who are governed or covered under any other Provident Fund Rules.

5. *Realization of subscription.*—(1) Every servant to whom these rules apply shall subscribe to the Provident Fund. Subscription to the Provident Fund shall be recovered by means of deduction of the amount from salary bill of each month and the amount shall be in whole rupees.

(2) Notwithstanding anything contained in rule 3, a subscriber shall subscribe monthly to the provident fund except during the period when he is under suspension:

Provided that a subscriber may, at his option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary equal to or less than half pay or half average pay:

Provided further that a subscriber on re-instatement, after a period passed under suspension, shall be allowed the option of payment in lump-sum or in installments any sum not exceeding the maximum amount of arrear subscription payable for that period.

(3) If a servant admitted to the benefit of the Provident Fund was previously a subscriber to any other contributory or non contributory Provident Fund of Central Government, the amount of his subscriptions and Government contribution in other Contributory Provident Fund or amount of his subscription in non Contributory Fund, as the case may be, together with interest thereon, shall be transferred to his credit in the Provident Fund.

(4) If a servant admitted to the benefit of the Provident Fund was previously a subscriber to any other Government Contributory Provident Fund or non Contributory Provident Fund, the amount of his subscription and the Government contribution in the Contributory Provident Fund or the amount of his subscription in the non Contributory Provident Fund, as the case may be, together with interest thereon, shall be transferred to his credit in the Provident Fund with the consent of the other Government.

**Note-1.**—The provisions of sub-rules (3) and (4) shall not apply to a person who has retired and is subsequently re-employed, with or without a break in service, or to a person who was holding the former appointment on contract.

**Note-2.**—The provisions of this rule shall, however, apply to persons who are appointed without break, whether temporarily or permanently to a post carrying the benefit of these rules after resignation or retrenchment from service under another Government department of Central Government or under the State Government.

**Note-3.**—The provisions of sub-rules (4) shall also apply *mutatis mutandis* to persons who are transferred, without any break, from service under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation registered under Societies Registration Act, 1860.

6. *Transfer to foreign service or deputation out of India.*—When a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation out of India, he shall remain subject to rules of the Provident Fund in the same manner as if he was not so transferred or sent on deputation.



**7. Nominations.**—(1) A subscriber shall, at the time of joining the Provident Fund, send to the Chief Executive Officer through Head of Office a nomination, conferring one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Provident Fund in the event of his death, before the amount has become payable or having become payable has not been paid:

Provided that, if, at the time of making the nomination the subscriber has a family, the nomination shall not be in favour of any person or persons other than the member of his family:

Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other Provident Fund to which he was subscribing before joining the Provident Fund shall, if the amount to his credit in such other Fund has been transferred to his credit in this Provident Fund, be deemed to be a nomination duly made under this rule until he makes a nomination in accordance with this rule.

(2) If a subscriber nominates more than one person under sub-rule(1), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Provident Fund at any time.

(3) Every nomination shall be made in the Form set forth in the Schedule appended to these rules.

(4) A subscriber may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Chief Executive Officer. The subscriber shall, alongwith such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(5) A subscriber may provide in a nomination,—

- (a) in respect of any specified nominee, that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination:

provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount or share payable to each of such person in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee; and

- (b) that the nomination shall become invalid in the event of happening of a contingency specified therein:

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of his family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause(a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-rule (5) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-rule (5) or the proviso therefore, the subscriber shall send to the Chief Executive Officer a notice in writing cancelling the nomination, together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Chief Executive Officer.

8. *Subscriber's Accounts.*—(1) An account shall be opened in the name of each subscriber and Provident Fund Account number allotted to the subscriber shall be entered in his service book. The amount of subscription, interest thereon, employer contribution and interest thereon, advances and withdrawals from the Provident Fund shall be shown in the account of the subscriber.

(2) A statement showing the balances appearing in the account of subscriber at the close of financial year shall be supplied to each subscriber every year.

9. *Contribution by Authority.*—The Authority shall make contribution at the end of every month to the Provident Fund account of each subscriber of an amount equal to ten percent of his emoluments expressed in whole rupees or as the State Government by general or special order may specify:

Provided that no contribution shall be payable in respect of any period for which the subscriber is permitted under the rules not to, or does not subscribe to the Provident Fund.

10. *Interest.*—(1) The Authority shall pay to the credit of the account of a subscriber, interest, at such rate as the Government may from time to time prescribe for the payment of interest on subscription to the General Provident Fund, on the amount to his credit in the Provident Fund.

(2) Interest shall be credited on the 31<sup>st</sup> March of each year in the following manner:—

- (i) on the amount to the credit of a subscriber on the 31<sup>st</sup> March of the preceding year, reduced by the amount if any, advance/withdrawn during the current year;
- (ii) on sums withdrawn during the current year interest from 1st April of the current year upto the last day of the month proceeding the month of withdrawal ;
- (iii) on all the sums credited to the subscriber's account after 31<sup>st</sup> March of the proceeding year interest from the date of deposit upto 31<sup>st</sup> March of the current year;
- (iv) the total amount of interest shall be rounded off to the nearest rupee (fifty paise counting as next higher rupee):

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall there upon be credited under this rule in respect of only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, upto the date on which the amount standing to the credit of the subscriber become payable.

(3) In addition to any amount to be paid under rule 21, interest thereon upto the end of the month preceding that in which the payment is made, or upto the end of sixth month after the month in which such amount became payable whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid:

Provided that, where the Chief Executive Officer has intimated to the person or his agent the date on which he is prepared to make payment in cash, or has posted a cheque in payment to that

person, interest shall be payable only upto the end of the month preceding the date so intimated, or the date of posting the cheque, as the case may be.

**11. *Advances from the Provident Fund.***—(1) The Chief Executive Officer may sanction the payment to any subscriber of an advance not exceeding six month's pay or half the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Provident Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes :—

- (a) to pay expenses in connection with illness, confinement or a disability, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent upon him;
- (b) to meet the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent upon him in the following cases, namely :—
  - (i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and
  - (ii) for any medical, engineering or other technical or specialized course in India beyond High School stage; provided that the course of study is for not less than three years;
- (c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;
- (d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Government source;
- (e) to meet the cost of subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part; and
- (f) to purchase consumer durable articles such as TV, VCR/VCP, washing machines, cooking range, Geysers and computers.

(2) The Authority may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of any advance if it is satisfied that the subscriber concerned require the advance for reasons other than those mentioned in sub-rule (1).

(3) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-rule (1) or until re-payment of the last installment of any previous advance:

Provided that an advance shall in no case exceed the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Provident Fund.

(4) When an advance is sanctioned under sub-rule (3) before re-payment of last installment of any previous advance is completed, the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the installments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

**12. Recovery of advances.**—(1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly installments as the Chief Executive Officer may direct, but such number shall not be less than twelve and more than twenty, unless the subscriber elects to pay in less than twelve. In special cases, where the amount of advance exceeds six months' pay of the subscriber under sub-rule (3) of rule 11, the Chief Executive Officer may fix such number of installments to be more than twenty four but in no case more than thirty six. A subscriber may, at his option, make re-payment in smaller number of installments than prescribed.

(2) The recovery shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn. Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent, while he is in receipt of subsistence grant or is on leave for ten days or more in a calendar month which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay, as the case may be. The recovery, may be postponed on the subscriber's written request, by Chief Executive Officer during the recovery of an advance of pay granted to the subscriber.

**13. Wrongful use of advance.**—Notwithstanding anything contained in these rules, if the Chief Executive Officer has reasons to doubt that money drawn as an advance from the Provident Fund under rule 11 has been utilized for a purpose other than that for which sanction was given to the drawl of money, he shall communicate to the subscriber the reasons for his doubt and require him to explain in writing, within 15 days of the receipt of such communication, whether the advance has been utilized for the purpose for which sanction was given to the drawl of the money. If the Chief Executive Officer is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of fifteen days, the Chief Executive Officer shall direct the subscriber to re-pay the amount in question to the Provident Fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one sum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If, however, the total amount to be repaid is more than half the subscribing emoluments, recoveries shall be made in monthly installments of moieties of his emoluments till he re-pays the entire amount.

**Note.**—The term "emoluments" in this rule does not include subsistence grant.

**14. Withdrawal from the Provident Fund.**—(1) Subject to the conditions specified therein, withdrawals may be sanctioned by the Chief Executive Officer for special reasons under sub-rule (3) of rule 11, at any time.—

(I) after the completion of fifteen years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Provident Fund, for one or more the following purposes, namely:—

(a) meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely:—

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialized course in India beyond the High School stage; and

(b) meeting the expenditure in connection with betrothal/marriage of the subscriber or his sons or daughters, and any other female relation actually dependent on him;

(c) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(d) meeting the cost of consumer durables such as TV, VCR/VCP, washing machines, cooking range, Geysers and computers;

(II) during the service of a subscriber from the amount of subscription and interest thereon standing to his credit in the Provident Fund for one or more of the following purposes, namely:—

(a) constructing or acquiring a suitable house or ready built flat for his residence including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or flat by the Authority or a house of a Co-operative Society;

(b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken to construct or acquire a suitable house or ready built flat for his residence;

(c) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber;

(d) renovating, additions or alterations or up keep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from the Authority at a place other than the place of duty;

(e) purchasing a house site to construct a house thereon for his residence; and

(f) constructing a house on a site purchased under clause (e);

**Note-1.**—The amount of withdrawal sanctioned under sub-clause (b) of clause (II) shall not exceed  $\frac{3}{4}$ th of the balance on the date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (a) of clause (II) reduced by the amount of previous withdrawals.

**Note-2.**—Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this rule. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (f) of clause (II) for completion of the same house shall be allowed upto the limit laid down under Note-1.

**Note-3.**—A withdrawal under this rule shall not be sanctioned if an advance under rule- 11 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

**15. Conditions for withdrawal.**—(1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in rule 14 from the amount standing to his credit in the Provident Fund shall not ordinarily exceed one half of the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Provident Fund or six month's pay, whichever is less. The Chief Executive Officer may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto  $\frac{3}{4}$  in the case of withdrawals under clause (I) and 90% in the case of withdrawals under clause (II) of sub-rule (1) of rule 14 of the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Provident Fund having due regard to,—

- (i) the object for which the withdrawal is being made;
- (ii) status of the subscriber; and
- (iii) amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber.

**16. Conversion of an advance into a withdrawal.**—A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under rule 11 for any of the purposes specified in sub-rule (1) of rule 14 may convert, at his discretion by written request addressed to the Chief Executive Officer the balance outstanding against it into a final withdrawal, on his satisfying the conditions laid down in rules 14 and 15.

**Note-I.**—For the purpose of sub-rule (1) of rule 15, the amount of subscription with interest thereon standing to the credit of the subscriber in the account at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance. Each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion.

**17. Final withdrawal of accumulations in the Provident Fund.**—When a subscriber quits the service, the amount standing to his credit in the Provident Fund shall, subject to any deduction under rule 20 become payable to him:

Provided that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently re-instated in the service shall, if required to do so by the Authority, re-pay any amount paid to him from the Provident Fund in pursuance of this rule, with interest thereon at the rate provided in rule 10 and in the manner provided in the proviso to rule 18. The amount so re-paid shall be credited to his account in the Provident Fund, the part which represents his subscriptions and interest thereon, and part of which represents Authority's contribution with interest thereon, being accounted for in the manner provided in rule-8.

**18. Exceptions.**—A subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed, with or without break in service, shall not be deemed to quit the service, when he is transferred without any break in service to a new post under a State Government or in another department of the Central Government (in which he is governed by another set of Provident Fund Rules) and without retaining any connection with his former post. In

such a case, his subscription and Authority's contribution, together with interest thereon shall be transferred,—

- (a) to his account in the other Provident Fund in accordance with the rules of the Provident Fund, if the new post is in another department of Government, or
- (b) to a new account under the State Government concerned if the new post is under a State Government and State Government consents by general or special order, to such transfer of his subscriptions, the Authority's contribution and interest.

**19. Retirement of subscriber.—**When a subscriber—

- (a) has proceeded on leave preparatory to retirement, or
- (b) while on leave, has been permitted to retire or declared by a competent medical authority to be unfit for further service, the amount of subscription and interest thereon standing to his credit in the Provident Fund shall, upon application made by him in that behalf to the Chief Executive Officer, become payable to the subscriber:

Provided that the subscriber, if he returns to duty, shall, except where the Authority decided otherwise, repay to the Provident Fund for credit to his account, the amount paid to him from the Provident Fund in pursuance of this rule with interest thereon at the rate provided in rule 10 in cash or securities, by installments or otherwise, by recovery from his emoluments or otherwise, as may be directed by the Chief Executive Officer an advance for the grant of which, special reasons are required under sub-rule (3) of rule 11.

**20. Procedure on death of subscriber.—**Subject to any deduction under rule 20, on the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable, before payment has been made;

(i) when the subscriber leaves a family,—

- (a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of rule 7 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Provident Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;
- (b) if no such nomination in favour of a member or members of the family, of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of amount standing to his credit in the Provident Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares:

Provided that no share shall be payable to—

- (1) sons who have attained majority;
- (2) sons of a deceased son who have attained majority;

- (3) married daughters whose husbands are alive;
  - (4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive;
- if there is any member of the family other than those specified in items (1), (2), (3) and (4):

Provided also that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of item (1) of the first proviso.

- (ii) when the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of rule 7 in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Provident Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

**21. Deduction.**— Subject to condition that no deduction may be made which reduces the credit by more than the amount of any contribution by the Authority with interest thereon credited under rules 9 and 10, before the amount standing to the credit of the subscriber in the Provident Fund is paid out of the Provident Fund,—

- (I) the Government may direct the deduction there from and payment to the Authority of—
  - (i) all amounts representing such contribution and interest, if the subscriber is dismissed from service due to misconduct, insolvency or in efficiency:

Provided that where the government is satisfied that such deduction would cause exceptional hardship to the subscriber, it may, by order, exempt from such deduction and amount not exceeding two third of the amount of such contribution and interest which would have been payable to the subscriber, if he had retired on medical grounds:

Provided further that if any such order of dismissal is subsequently cancelled, the amount so deducted shall, on his reinstatement in the service be replaced to his credit in the Provident Fund.

- (ii) all amounts representing such contribution and interest, if the subscriber within five years of commencement of his service as such, resigns from the service or cease to be an employee of the Authority otherwise than by reasons of death, superannuation or a declaration by a competent medical authority that he is unfit for further service, or the abolition of the post or the reduction of establishment.

- (II) the Government may direct the deduction therefrom and payment to the Authority of any amount due under a liability incurred by a subscriber to the Authority.

**NOTE-1.**— For the purpose of sub-clause (ii) of clause (I) of this rule,—

- (a) the period of five years shall be reckoned from the commencement of the subscriber's continuous service under the Authority;



- (b) resignation from service in order to take appointment in another department of the Central Government or under the State Government or under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860 without any break and with proper permission of the Authority, shall not be treated as resignation from service of the Authority.

**Note-2.**—The powers of the Government under this rule may, in respect of the amounts referred to therein, also be exercised by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-rule (3) of rule-11.

**22. Manner of payment of amount in the Provident Fund.**—(1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the Provident Fund or the balance thereof after deduction under rule 20 becomes payable, it shall be the duty of the Chief Accounts Officer after satisfying himself when no such deduction has been directed under this rule, that no deduction is to be made, to make payment on receipt of a written application in this behalf.

(2) To enable a subscriber to submit an application for withdrawal of the amount in the Provident Fund, the Chief Executive Officer shall send to every subscriber necessary forms. The subscriber shall submit the application to the Chief Executive Officer through Chief Accounts Officer.

(3) The final payment to the subscriber shall be sanctioned by the Chief Executive Officer immediately after fulfilling the requisite formalities.

**23. Application of Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 for matters not specified in these rules.**—The provisions of Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, as amended from time to time, shall be applicable to the employees of the Authority governed under these rules, in respect of the matters not specifically provided and which are not inconsistent with the provisions made under these rules.

**24. Repeal and savings.**—(1) The Himachal Pradesh Housing Board Contributory Provident Fund Rules, 1982 are thereby repealed :

Provided that anything done or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

**SCHEDULE**  
**[See Rule 7 (3)]**

Account No. \_\_\_\_\_

I, \_\_\_\_\_ hereby nominate the person(s) mentioned below who is/are member (s)/non-member(s) of my family as defined in rule 2 of the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (Employees Contributory Provident Fund) Rules 2005, to receive the amount that may stand to my credit in the Provident Fund as indicated below, in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid.

| Name and full address or nominees (s) | Relationship with the subscriber | Age of the nominee(s) | Share payable to each nominee | Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid | Name, address and relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his/her predeceasing the subscriber | If the nominee is not a member of the family as provided in rule 2, indicate the reasons |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|
| 1                                     | 2                                | 3                     | 4                             | 5  | 6  | 7  |
|                                       |                                  |                       |                               |  |  |  |
|                                       |                                  |                       |                               |  |  |  |
|                                       |                                  |                       |                               |  |  |  |
|                                       |                                  |                       |                               |  |  |  |
|                                       |                                  |                       |                               |  |  |  |
|                                       |                                  |                       |                               |  |  |  |
|                                       |                                  |                       |                               |  |  |  |
|                                       |                                  |                       |                               |  |  |  |
|                                       |                                  |                       |                               |  |  |  |

Dated this.....day of.....200.....at.....

Signature of the subscriber.....

Name in Block letters.....

Designation.....

Two witnesses to signature

Name and address

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Reverse of the form)

Space for use by the Head of Office/Pay & Accounts Office

Nomination by Sh./Smt./ Kumari \_\_\_\_\_ Designation \_\_\_\_\_

Date of receipt of nomination \_\_\_\_\_

Signature of Head of Office/Pay & Accounts Officer

Designation \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Instruction for the subscriber—

- (a) Your name may be filled in.
- (b) Name of the fund may be completed suitably.
- (c) Definition of term “family” as given in the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (Employees Contributory Provident Fund) Rules 2005, is reproduced below.

“Family” means—

- (i) in the case of male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sister, deceased son’s widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grandparent :

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber’s family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Chief Executive Officer that she shall continue to be so regarded.

- (ii) in the case of female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son’s widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grandparents:

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Chief Executive Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber’s family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

**Note**—“Child” means legitimate/illegitimate child and includes an adopted child where adoption is recognized by the personal law governing the subscriber or a ward under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), who lives with the servant of the Authority and is treated as a member of the family and to whom the servant has, through a special will, given the same status as that of a natural born child.

- (a) Col. 4—If only one person is nominated the words “ in full” should be written against the nominee. If more than one person is nominated, the share payable to each nominee over the whole amount of the Provident Fund shall be specified.
- (b) Col. 5—Death of nominee (s) should not be mentioned as contingency in this column.
- (c) Col. 6—do not mention your name.
- (g) Draw line across the blank space below last entry to prevent insertion of any name after you have signed.

By order

Sd/-  
Secretary.